CEASI TIMES

7th July 2025

HINDI

CEASI

CENTRES OF EXCELLENCE FOR AGRICULTURE SKILLS IN INDIA

CEDSI
CENTRE OF EXCELLENCE FOR DAIRY SKILLS IN INDIA

CEFMI
Centre of Excellence for Farm Mechanization Skills in India

CEHSI
Centre of Excellence for Horticulture Skills in India

www.ceasi.in

हमारे बारे में

हम कौन हैं:

"सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर स्किल्स इन इंडिया (CEASI)" एक स्वायत्त संस्था है, जो "एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया (ASCI)" के अधीन कार्य कर रही है। यह संस्था कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के तहत कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कार्यरत किसानों, मजदूरी श्रमिकों, स्वरोजगार में लगे पेशेवरों, विस्तार कार्यकर्ताओं आदि के लिए कौशल विकास और क्षमता निर्माण का कार्य करती है।

CEASI कृषि के विभिन्न उप-क्षेत्रों में स्थापित उत्कृष्टता केंद्रों की शीर्ष संस्था है, जैसे कि:

- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डेयरी स्किल्स इन इंडिया (CEDSI)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्टिकल्चर स्किल्स इन इंडिया (CEHSI)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फार्म मेकनाइजेशन स्किल्स इन इंडिया (CEFMI)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट रेज़िलिएंट एग्रीकल्चर (CoE-CRA)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर (CoE-AI)

हम क्या करते हैं:

- **कौशल विकास और क्षमता निर्माण:** कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में हितधारकों की आवश्यकताओं के आधार पर क्षमता निर्माण।
- **ज्ञान प्रबंधन:** वर्क्फोर्स मानकों को समर्थन देने हेतु QPs, NOS, स्किल गैप रिपोर्ट और न्यूज़लेटर्स का विकास।
- **अनुसंधान:** उद्योग की मांगों के अनुसार आवश्यकताओं की पहचान और कौशल अंतर को पाटने के लिए अनुसंधान।
- **नीति समर्थन और परामर्श सेवाएं:** नवाचार साझा करने और क्षेत्रीय चुनौतियों को हल करने हेतु नेटवर्क् का निर्माण।

हमारा विज़न

एक स्वायत्त उत्कृष्टता संस्थान जो कृषि में उच्च कौशलयुक्त कार्यबल विकसित करने के लिए समर्पित है, नवाचार, तकनीकी प्रगति और सतत प्रथाओं के माध्यम से भारतीय कृषि की समृद्धि और लचीलापन बढ़ाने के लिए कार्यरत है।

हमारा मिशन

राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर उन्नत कृषि पद्धतियों में कौशल विकास के लिए अग्रणी संगठन के रूप में उभरना, जो सततता, लाभप्रदता, क्षमता निर्माण, ज्ञान प्रसार, नीति समर्थन और नवाचार आधारित अनुसंधान के माध्यम से कृषि क्षेत्र के समग्र विकास को प्रोत्साहित करता है।

CEASI का प्रभाव:

CEASI भारतीय कृषि में एक परिवर्तनकारी बदलाव ला रहा है, जो व्यक्तियों को सशक्त बनाने, कौशल को निखारने और देशभर में समुदायों को उन्नत करने का कार्य कर रहा है।

- **15+ राज्य**
- **15 एफपीओ को प्रशिक्षित और सहयोग प्रदान किया गया**
- **20,000 कृषि / डेयरी पेशेवरों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया**
- **5000+ उद्यमियों को प्रशिक्षित किया गया**
- **3000+ महिलाओं को सशक्त बनाया गया**
- **30,000+ जीवन को प्रभावित किया गया**

पापुम पारे में ऑयल पाम रोपण और कस्टम हायरिंग सेंटर का शुभारंभ

पापुम पारे जिले के बंदरदेवा सर्कल के गोरूबांदा में एक मेगा ऑयल पाम रोपण कार्यक्रम और कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) का उद्घाटन हुआ। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – ऑयल पाम (NMEO-OP) के तहत आयोजित किया गया, जिसे अरुणाचल प्रदेश सरकार के कृषि विभाग और पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने मिलकर आयोजित किया।

इस कार्यक्रम में कृषि एवं संबद्ध विभागों के मंत्री श्री गेब्रियल डी वांगसू मुख्य अतिथि और जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती नबाम याकुम विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारी, जैसे IAS अधिकारी श्रीमती विशाखा यादव भी उपस्थित थीं।

कस्टम हायरिंग सेंटर का उद्देश्य आधुनिक कृषि मशीनरी को किसानों के लिए सुलभ बनाना है, जिससे खेती में यंत्रीकरण को बढ़ावा मिलेगा और उत्पादकता में सुधार होगा। ऑयल पाम रोपण अभियान का लक्ष्य देश में खाद्य तेल उत्पादन को बढ़ावा देना भी है।

यह संयुक्त पहल ग्रामीण विकास, किसान सशक्तिकरण और पूर्वोत्तर भारत में तकनीकी रूप से उन्नत, आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम है।

हमीरपुर की महिला स्वयं सहायता समूहों को खेती के लिए मिलेंगे ड्रोन

खेती को आधुनिक बनाने और ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले की चार महिला नेतृत्व वाली स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को 'नमो ड्रोन दीदी' योजना के तहत ड्रोन दिए जाएंगे। यह पहल जिला कृषि विभाग द्वारा संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़कर उनकी आय बढ़ाना और खेती को आसान बनाना है।

ये ड्रोन तरल उर्वरक और कीटनाशकों को खेतों में छिड़कने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, और प्रत्येक ड्रोन लगभग 20 एकड़ भूमि को कवर कर सकता है। प्रत्येक समूह की महिलाओं को ड्रोन चलाने और रखरखाव का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिससे वे सटीक खेती (Precision Farming) कर सकेंगी और मेहनत भी कम होगी।

जिला कृषि अधिकारी राजेश राणा के अनुसार, यह योजना न केवल पर्यावरण-अनुकूल खेती को बढ़ावा देती है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के लिए नए व्यवसाय के अवसर भी खोलती है।

यह पहल समावेशी विकास, कृषि यंत्रीकरण और महिला उद्यमिता को आगे बढ़ाने की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम है।

महाराष्ट्र में पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लॉन्च, टिकाऊ खेती को मिलेगा बढ़ावा

महाराष्ट्र ने राज्य का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लॉन्च कर कृषि यंत्रीकरण और टिकाऊ खेती की दिशा में एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है। 45 हॉर्सपावर का यह ई-ट्रैक्टर ठाणे आरटीओ में पंजीकृत किया गया और इसका उद्देश्य खेती की लागत को कम करते हुए स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है।

यह ट्रैक्टर खासतौर पर खेती के लिए डिजाइन किया गया है और इसकी संचालन लागत बहुत कम है। जहां डीजल ट्रैक्टर से एक एकड़ खेत जोतने में ₹1,200–₹1,500 लगते हैं, वहीं इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर से यही काम केवल ₹300 में हो जाता है। साथ ही, इसके रखरखाव की लागत भी कम है, जिससे किसानों को रोज़ की बचत होती है।

राज्य की इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2025 के तहत ई-ट्रैक्टर पर ₹1.5 लाख तक की सब्सिडी, टोल छूट और ब्याज-मुक्त ऋण की सुविधा दी जा रही है।

यह पहल न केवल कार्बन उत्सर्जन को घटाने में सहायक है, बल्कि ग्रामीण आय को भी बढ़ावा देगी। महाराष्ट्र इस कदम के साथ देश में स्वच्छ और किफायती कृषि की दिशा में एक नई राह दिखा रहा है।

उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म सिंचाई बनी कृषि बदलाव की प्रमुख ताकत

उत्तर प्रदेश सरकार 'प्रति बूंद अधिक फसल' योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई (माइक्रो इरिगेशन) को बढ़ावा देकर कृषि क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन ला रही है। इस योजना का लक्ष्य 2028 तक सूक्ष्म सिंचाई क्षेत्र को 30,000 हेक्टेयर से बढ़ाकर 7.5 लाख हेक्टेयर करना है। यह पहल वर्ल्ड बैंक के 2030 वॉटर रिसोर्स ग्रुप के सहयोग से यूपी एक्सेलरेटर कार्यक्रम के अंतर्गत चल रही है।

ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर और रेन गन जैसी तकनीकों से 30% से 70% तक पानी की बचत होती है, मिट्टी का कटाव कम होता है और खाद-कीटनाशक की जरूरत भी घटती है। इससे खेती ज्यादा टिकाऊ और लागत प्रभावी बनती है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार, हर ₹1 के निवेश पर किसान ₹1.5 से ₹2 तक की उपज प्राप्त कर सकते हैं।

इस मॉडल का एक अहम पहलू है डिजिटल पोर्टल, जिससे किसानों को सब्सिडी प्राप्त करने और तकनीक अपनाने में आसानी होती है। अब तक 3.5 लाख से ज्यादा किसान इस पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं।

यह मॉडल पूरे भारत के लिए जल-संरक्षण आधारित, उच्च उत्पादकता वाली कृषि का उत्कृष्ट उदाहरण बन सकता है।

उत्तराखंड में मिलेट, कीवी और ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा, किसानों की आमदनी बढ़ाने पर जोर

उत्तराखंड सरकार पारंपरिक और उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राज्य मिलेट मिशन के तहत 2022 से मण्डुआ (फिंगर मिलेट) की खरीद शुरू हुई, जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मिड-डे मील और आंगनवाड़ी पोषण कार्यक्रमों में शामिल किया गया। मण्डुआ का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2021 में ₹2,500 प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2024 में ₹4,200 कर दिया गया है। मण्डुआ संग्रह केंद्रों की संख्या 23 से बढ़कर 270 हो गई है। 2025–31 के लिए दो चरणों में लागू की गई राज्य मिलेट नीति के तहत 11 जिलों में 70,000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जाएगा, जिसमें मण्डुआ, झंगोरा, रामदाना, कौनी और चीन जैसी फसलें शामिल हैं।

बागवानी क्षेत्र में, 2025–31 के लिए लागू की गई कीवी नीति के अंतर्गत 11 जिलों में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए ₹12 लाख प्रति एकड़ लागत पर 70% राज्य सहायता प्रदान की जा रही है। ₹894 करोड़ की कुल परियोजना लागत निर्धारित की गई है। वहीं, मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास कार्यक्रम के तहत ड्रैगन फ्रूट योजना 2025 से 2028 तक सात जिलों में लागू की गई है, जिसमें प्रति एकड़ ₹8 लाख लागत पर 80% राज्य सहायता दी जा रही है। दोनों योजनाओं में आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों से खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़े और टिकाऊ कृषि को बल मिले।

जम्मू-कश्मीर में बागवानी और कृषि को बढ़ावा देने के लिए केंद्रित प्रयास

एक उच्च स्तरीय दौरे के दौरान जम्मू-कश्मीर में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों को सशक्त बनाने की दिशा में किए जा रहे नवाचारों की समीक्षा की गई और केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया गया। जम्मू-कश्मीर के शालिमार परिसर में अधिकारियों ने शीघ्र फल देने वाली सेब की किस्मों, ओलावृष्टि से सुरक्षा प्रणाली, वैज्ञानिक छंटाई और स्मार्ट जल- पोषक तत्व प्रबंधन जैसी उन्नत तकनीकों का अवलोकन किया। किसानों ने उत्पादन वृद्धि और आय में सुधार की सफल कहानियां साझा कीं, जबकि छात्रों ने कोल्ड स्टोरेज समाधान और गुणवत्ता युक्त उत्पाद प्रदर्शित किए।

बाद में आयोजित हितधारक बैठक में केसर की खेती के लिए सिंचाई, कीट नियंत्रण सुरक्षा, सस्ते इनपुट, फसल बीमा और कोल्ड चेन विकास जैसी प्रमुख मांगें उठाई गईं। जवाब में, क्लीन प्लांट सेंटर्स की स्थापना, निजी नर्सरियों को प्रोत्साहन, और HADPL के तहत बुनियादी ढांचे के विकास की योजनाओं की घोषणा की गई। साथ ही, उचित मूल्य निर्धारण, लॉजिस्टिक सुधार और गुणवत्ता नियंत्रण पर विशेष जोर दिया गया। यह दौरा जम्मू-कश्मीर को बागवानी का हब बनाने और किसानों की सतत समृद्धि सुनिश्चित करने की केंद्र की क्षेत्रीय रणनीति को दर्शाता है।

फसल विविधिकरण और किसान सशक्तिकरण के माध्यम से पंजाब में बागवानी को नया विस्तार

पंजाब सरकार बागवानी क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए फसल विविधिकरण पर विशेष ध्यान दे रही है, जिससे उत्पादकता, आय और बाजार पहुंच में सुधार हो सके। हाल ही में पंजाब सिविल सचिवालय में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में प्रमुख बागवानी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई, जिनका उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना, उन्नत तकनीकों को अपनाना और किसानों को बेहतर बाजार सुविधा प्रदान करना है।

बैठक में यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया कि किसानों को सरकारी योजनाओं, नई तकनीकों और सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों की जानकारी समय पर और सटीक रूप से उपलब्ध हो। इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों, जागरूकता शिविरों और डिजिटल माध्यमों के उपयोग को तेज करने के निर्देश दिए गए। यह प्रयास किसानों को आधुनिक विधियों को अपनाने और सरकारी सहायता का पूरा लाभ उठाने में सक्षम बनाएंगे। यह पहल पंजाब में कृषि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और टिकाऊ बागवानी को बढ़ावा देने की दिशा में एक ठोस कदम है।

चार वर्षों में बागवानी योजनाओं के तहत ₹220 लाख से अधिक की सहायता वितरित

धर्मपुरी में बागवानी विभाग द्वारा गत चार वर्षों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 16,700 लाभार्थियों को कुल ₹227.69 लाख की सहायता राशि वितरित की गई है। मुख्यमंत्री सब्जी उद्यान योजना के तहत 1,313 छत पर बागवानी किट्स ₹450 की रियायती दर पर वितरित की गईं। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को ₹30 प्रति पैकेट की दर से 5,200 सब्जी बीज पैकेट और ₹75 मूल्य की माइक्रो ग्रीन किट्स 4,500 लाभार्थियों को प्रदान की गईं।

इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु राज्य बागवानी विकास योजना के तहत कोविड काल के दौरान किसानों को सब्जी और फल विक्रय हेतु मोबाइल वाहनों की सुविधा दी गई। धर्मपुरी में 190 मोबाइल वाहनों को ₹15,000 प्रति वाहन की सब्सिडी के साथ कुल ₹28.5 लाख की लागत पर वितरित किया गया। ये पहलें रसोई उद्यान को बढ़ावा देने, पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने, आजीविका को समर्थन देने और बागवानी मूल्य श्रृंखला में अंतिम छोर तक पहुंच को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई हैं।

गुजरात में नए डेयरी और नमक सहकारी संस्थानों की शुरुआत, किसानों और उत्पादकों को मिलेगा सशक्तिकरण

सहकारिता मंत्रालय द्वारा गुजरात के आनंद में सरदार पटेल सहकारी डेयरी फेडरेशन की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य डेयरी क्षेत्र को संगठित दूध संग्रहण, उचित मूल्य निर्धारण और सर्कुलर इकॉनॉमी मॉडल के माध्यम से मजबूत करना है। यह नया मल्टी-स्टेट फेडरेशन किसानों को इनपुट सेवाएं और समान दूध खरीद सुनिश्चित करेगा, जिससे देशभर के डेयरी किसानों को लाभ मिलेगा।

इसके साथ ही, कच्छ जिला नमक सहकारी संस्था की स्थापना की गई है, जो गुजरात के नमक उत्पादकों (अगड़िया) को सशक्त बनाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि लाभ सीधे फील्ड स्तर पर काम करने वाले श्रमिकों तक पहुंचे। गुजरात देश के कुल नमक उत्पादन का 70% से अधिक योगदान करता है, जिसमें लगभग 30% उत्पादन लिटिल रण ऑफ कच्छ से होता है।

इस लॉन्च कार्यक्रम में सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती वर्ष को भी मनाया गया। कई प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, जिनमें अमूल के चीज और चॉकलेट प्लांट का ₹365 करोड़ का विस्तार, एनसीडीएफआई का मणिबेन पटेल भवन, और एनडीडीबी द्वारा निर्मित ₹45 करोड़ की रेडी-टू-यूज़ कल्चर (RUC) प्लांट शामिल हैं। इसके अलावा, एनडीडीबी के नए मुख्यालय भवन की आधारशिला भी रखी गई, जिससे सहकारिता क्षेत्र में पारदर्शिता और प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।

एनडीडीबी बनाएगा अरुणाचल प्रदेश में डेयरी क्षेत्र को सशक्त, दूध यूनियन और फेडरेशन का गठन

नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (NDDB) अरुणाचल प्रदेश के डेयरी क्षेत्र को मजबूती देने के लिए दूध यूनियन और राज्य स्तरीय डेयरी फेडरेशन की स्थापना करने जा रहा है। आधिकारिक बयान के अनुसार, यह कदम राज्य में डेयरी और संबद्ध क्षेत्रों के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा।

इस पहल के तहत, राज्य की पांच प्रमुख नदी घाटियों पर आधारित पांच दुग्ध यूनियन बनाई जाएंगी। इसकी शुरुआत लोहित नदी घाटी से होगी, जिसमें लोहित, नामसाई और लोअर दिबांग वैली जिले शामिल हैं। यह जानकारी एनडीडीबी कोलकाता के रीजनल हेड एस. रॉय ने नामसाई के चौखाम सर्कल में आयोजित एक प्रशिक्षण सत्र के दौरान दी। सिआंग, सुबनसिरी, कामेंग और तिरप नदी घाटियों में भी इसी प्रकार की यूनियन स्थापित करने की योजना है। बाद में ये सभी यूनियन मिलकर एक राज्य स्तरीय दुग्ध महासंघ का निर्माण करेंगी।

पशुपालन, पशु चिकित्सा और डेयरी विकास विभाग के निदेशक डी. लाँगरी ने लोहित घाटी सर्वेक्षण को 31 जुलाई, 2025 तक पूरा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि राज्य के कई जिलों में पर्याप्त डेयरी क्षमता होने के बावजूद डेयरी सहकारी समितियों का गठन धीमा है। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि लोहित मॉडल को एक आदर्श बनाकर राज्यभर में इसे दोहराया जाए, जिससे श्वेत क्रांति 2.0 को सफल बनाया जा सके।

गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (GADVASU) ने स्मार्ट डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा दिया

गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (GADVASU) ने डेयरी फार्मिंग में सेंसर-आधारित तकनीकों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इन तकनीकों का उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाना, पशु स्वास्थ्य सुधारना, और फार्म दक्षता में वृद्धि करना है।

Temperature Humidity Index (THI) सेंसर, गैस सेंसर, TDS मीटर, और अनाज में नमी मापने वाले मीटर जैसे रियल-टाइम मॉनिटरिंग उपकरणों के माध्यम से किसान अब सटीक और लाभदायक खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जिससे लागत घटती है और पशु कल्याण सुनिश्चित होता है।

इस पहल के तहत, Farmer FIRST Project के अंतर्गत मेहल कलां गांव में एक हैंड्स-ऑन जागरूकता और प्रदर्शन शिविर का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने किसानों को इन तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया।

किसानों को यह बताया गया कि कैसे रियल-टाइम डेटा की मदद से रोगों के प्रारंभिक लक्षण, गर्मी से तनाव, पानी की शुद्धता, और प्रजनन दक्षता का समय पर पता लगाया जा सकता है।

इन उपकरणों को 9 डेयरी फार्मों में स्थापित किया गया है और 30 दिनों तक डेटा संग्रह किया जाएगा, जिसके आधार पर किसानों को विशेष सलाह दी जाएगी।

यह पहल पंजाब में पारंपरिक डेयरी प्रथाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने में GADVASU की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिससे टिकाऊ और डेटा-आधारित डेयरी खेती को बढ़ावा मिल सके।

जम्मू-कश्मीर में पशुपालन और मत्स्य क्षेत्र की समीक्षा, अवसंरचना, सहकारिता और बाज़ार से जुड़ाव पर ज़ोर

मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर सरकार के साथ मिलकर श्रीनगर स्थित सिविल सचिवालय में पशुपालन और मत्स्य क्षेत्रों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया। चर्चा का मुख्य उद्देश्य अवसंरचना सुदृढ़ करना, सहकारी संस्थाओं को पुनर्जीवित करना और किसानों के लिए बाजार तक पहुंच बढ़ाना था।

इस अवसर पर जम्मू के सतवारी में 50,000 लीटर प्रति दिन क्षमता वाला UHT मिल्क प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। अधिकारियों ने डेयरी कार्यों के संगठन, सहकारी समितियों के पुनर्निर्माण और ट्राउट व मटन सेक्टर में वैल्यू चेन विकसित करने पर बल दिया।

जम्मू-कश्मीर में पशुधन और मत्स्य पालन का राज्य के GDP में 6.25% योगदान है। यहां 144 लाख से अधिक पशुधन और वार्षिक 2,875 TMT दूध उत्पादन होता है। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम (HADP) के तहत ₹1,364 करोड़ केवल पशुपालन और मत्स्य क्षेत्रों के लिए आवंटित किए गए हैं।

प्रमुख उपलब्धियों में 96 लाख टीकाकरण, 2.9 लाख बीमित पशु, 50 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों की तैनाती, 1,800 पशु सखी, और 500 हाइड्रोपोनिक चारा इकाइयों की स्थापना शामिल है। किसान साथी और दक्ष किसान LMS प्लेटफार्म के माध्यम से डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है।

भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता: टिकाऊ कृषि विकास पर जोर

भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर उन्नत स्तर पर बातचीत चल रही है, जिसमें कृषि क्षेत्र एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। दोनों देश सहयोग के नए अवसर तलाश रहे हैं, वहीं भारत कृषि क्षेत्र में दीर्घकालिक स्थिरता और समावेशी विकास को प्राथमिकता दे रहा है।

भारत के करोड़ों छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए, सरकार चाहती है कि व्यापार समझौते ग्रामीण आजीविका, खाद्य सुरक्षा और टिकाऊ विकास से जुड़े हों। इसके लिए कृषि यंत्रीकरण, तकनीकी नवाचार और आधुनिक खेती की पद्धतियों को प्रमुखता दी जा रही है।

भारत का दृष्टिकोण यह है कि अचानक बाजार खुलने की बजाय, क्षमता विकास के ज़रिए किसानों को सशक्त किया जाए। यह रणनीति निवेश, ज्ञान-विनिमय और मूल्य श्रृंखला विकास में वैश्विक सहयोग का मार्ग खोल सकती है।

यंत्रीकरण और रणनीतिक साझेदारी पर ध्यान केंद्रित करके, भारत एक भविष्य-उन्मुख कृषि अर्थव्यवस्था की दिशा में अग्रसर है और अमेरिका जैसे साझेदारों के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध बनाने की दिशा में काम कर रहा है।

महाराष्ट्र सरकार अगले 5 साल में कृषि क्षेत्र में ₹25,000 करोड़ निवेश करेगी

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए अगले पांच सालों में ₹25,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की है। इस निवेश का उद्देश्य किसानों की लागत को कम करना और उत्पादन को बढ़ाना है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह घोषणा पंढरपुर में आयोजित 'कृषि पंढरी' कृषि प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में की। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत ड्रिप सिंचाई, आधुनिक कृषि यंत्र, खेत तालाब, पंप जैसी सुविधाएं किसानों को दी जाएंगी।

सरकार की योजना ग्रामीण सहकारी संस्थाओं को बहु-उद्देश्यीय संस्थाओं में बदलने की है, जो 18 तरह की कृषि सेवाएं दे सकेंगी। ये संस्थाएं किसानों को बाजार से जोड़ने में मदद करेंगी।

इसके अलावा भंडारण और कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाएं भी बढ़ाई जाएंगी, ताकि किसान अपनी उपज को बेहतर कीमतों पर बेच सकें। यह निवेश कृषि को लाभदायक और टिकाऊ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

किसानों को प्रत्यक्ष लाभांतरण कृषि क्षेत्र में बदलाव की कुंजी के रूप में प्रस्ताव

भारत की कृषि सब्सिडी प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता पर जोर देते हुए सुझाव दिया गया है कि सब्सिडी सीधे किसानों के खातों में दी जाए, न कि विभागों या बिचौलियों के माध्यम से। यह बदलाव किसानों को स्वतंत्र निर्णय लेने, टिकाऊ कृषि अपनाने और रासायनिक पदार्थों पर निर्भरता घटाने के लिए सक्षम बना सकता है। अंतरराष्ट्रीय उदाहरणों का हवाला देते हुए बताया गया कि प्रत्यक्ष लाभांतरण प्रणाली से किसान अपनी आवश्यकताओं के अनुसार संसाधनों का बेहतर प्रबंधन कर पाते हैं।

बताया गया कि वर्तमान में चल रही योजनाओं के तहत पात्र किसानों को ₹6,000 प्रतिवर्ष मिलते हैं, लेकिन यदि सरकार की पूरी कृषि सब्सिडी — विशेष रूप से ₹3 लाख करोड़ की उर्वरक सब्सिडी — सीधे किसानों को दी जाए, तो प्रत्येक परिवार को ₹30,000 से अधिक मिल सकता है। यह पहल प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने, रासायनों के उपयोग को घटाने और 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम हो सकता है।

जलवायु जोखिमों से सुरक्षा के लिए भारत का पहला वेदर डेरिवेटिव लॉन्च

भारत कृषि क्षेत्र को जलवायु जोखिमों से सुरक्षित करने के लिए अपना पहला वेदर डेरिवेटिव उत्पाद लॉन्च करने जा रहा है। यह उत्पाद किसानों और कृषि-आधारित उद्योगों को अनियमित वर्षा, सूखा और असामयिक मौसम जैसी परिस्थितियों से बचाव के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा। यह पहल नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज (NCDEX) और भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के बीच रणनीतिक साझेदारी के तहत शुरू की गई है। इसके अंतर्गत वास्तविक समय और ऐतिहासिक मौसम डेटा के आधार पर वर्षा आधारित वित्तीय अनुबंध विकसित किए जाएंगे, जो क्षेत्रीय जलवायु प्रवृत्तियों को सांख्यिकीय सटीकता से दर्शाएंगे।

यह नया उपकरण मौसमी और स्थान-विशेष डेरिवेटिव अनुबंधों के माध्यम से किसानों व संबद्ध क्षेत्रों को जलवायु अनिश्चितता से निपटने में सक्षम बनाएगा। यह कृषि, कृषि व्यवसाय और परिवहन तथा पर्यटन जैसे अन्य क्षेत्रों में सूचित निर्णय लेने में मदद करेगा। साझेदारी के अंतर्गत किसान उत्पादक संगठनों, व्यापारियों और नीति-निर्माताओं के लिए संयुक्त अनुसंधान, प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन गतिविधियाँ भी चलाई जाएंगी। यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जलवायु के प्रति लचीला बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अयोध्या के किसानों को सशक्त बनाना: टिकाऊ गन्ना खेती की ओर एक कदम

सश्वत मिठास पहल के तहत, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर स्किल्स इन इंडिया और UPL SAS लिमिटेड के साझेदारी में अयोध्या में टिकाऊ गन्ना खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य किसानों को पर्यावरण के अनुकूल खेती की विधियों में प्रशिक्षित करना है, जिससे पैदावार बढ़े और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो सके।

अब तक 397 किसानों का सर्वेक्षण किया गया है, ताकि उनकी मौजूदा खेती की पद्धतियों को समझा जा सके और सुधार के अवसरों की पहचान की जा सके। ज़मीनी स्तर पर किसानों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिए प्रदर्शन प्लॉट तैयार किए जा रहे हैं। इन प्लॉट्स पर जल प्रबंधन, मिट्टी की सेहत सुधारना और जैविक खादों का इस्तेमाल जैसे टिकाऊ खेती के सर्वोत्तम तरीके दिखाए जाते हैं।

किसानों की भागीदारी और जानकारी साझा करने के लिए अब तक 35 अनौपचारिक बैठकें, 2 औपचारिक बैठकें, 36 रिटेलर विज़िट और 4 फील्ड डे आयोजित किए जा चुके हैं। इन आयोजनों में किसान अपने अनुभव साझा करते हैं, सवाल पूछते हैं और टिकाऊ खेती की तकनीकों को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं।

इस परियोजना का मकसद है कि किसान जलवायु अनुकूल और पर्यावरण हितैषी तरीकों को अपनाएं। यह पहल न सिर्फ फसल की पैदावार बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है, बल्कि अयोध्या क्षेत्र में खेती को लंबे समय तक टिकाऊ और संतुलित बनाने में भी अहम भूमिका निभा रही है।

CEASI

CENTRES OF EXCELLENCE FOR
AGRICULTURE SKILLS IN INDIA

(CEASI), Unit No. 101, First Floor, Greenwoods Plaza, Block 'B' Greenwoods City, Sector-45, Gurugram, Haryana-122009

+91 74287 06078

info@cedsi.in

www.ceasi.in

@ceasi_india